महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल बनेंगे 1,57,815 मकान

रायपुर(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 57 हजार 815 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के संचालक एस. प्रकाश ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों को इस वर्ष योजना के तहत बनने वाले मकानों की जानकारी भी भेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश में बनने वाले कुल एक लाख 57 हजार 815 मकानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के 74 हजार 696, अनुसूचित जाति वर्ग के 20 हजार 042, अल्पसंख्यक वर्ग के 850 और अन्य वर्गों के हितग्राहियों के 62 हजार 227 मकान शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष में बालोद, बस्तर, कांकेर, सूरजपुर और कोरिया जिले में कुल सात-सात हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में साढ़े नौ हजार, बलरामपुर-रामानुजगंज में चार हजार, बेमेतरा और मुंगेली में पांच-पांच हजार, बीजापुर में 250, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद और रायगढ़ में नौ-नौ हजार, दंतेवाड़ा में तीन हजार, धमतरी में 3600, दुर्ग में 3557, गरियाबंद और राजनांदगांव में सात-सात हजार, जशपुर और कोरबा में आठ-आठ हजार, कबीरधाम में साढ़े चार हजार, कोंडागांव में 4100, नारायणपुर में 285, रायपुर में 523, सुकमा में डेढ़ हजार तथा सरगुजा जिले में 12 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई की घोषणा

रायपुर (आरएनएस)। आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद शशि थरूर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के मार्गदर्शन में आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने अपनी प्रदेश कार्यकारणी की घोषणा की जिसमें 10 लोगों को स्थान दिया गया है। इसमें मुकेश चंद्राकर और अजय श्रीवास्तव को समन्वयक, दीप सारस्वत को समन्वयक (सोशल मीडिया एवं संचार), स्नेहिल भारद्वाज को समन्वयक (कार्यक्रम व आयोजन), रवि गवलनी को समन्वयक (वित्तीय), सुदीप मैटर को समन्वयक (अनुसंधान), प्रणव दास को समन्वयक (समन्वय एआईपीसी इकाई) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं संभाग अनुसार शिल्पराज देवांगन को समन्वयक (सदस्यता विस्तार ,रायपुर), रणविजय सिंह देव को समन्वयक (सदस्यता विस्तार, सरगुज़ा), निखिल शाह को समन्वयक (सदस्यता विस्तार ,दुर्ग) नियुक्त किया गया है। आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रत्युष भारद्वाज, प्रदेश सचिव ऐश्वर्या सिंहदेव ने सभी पदाधिकारियो की नियुक्ति पर बधाई दी है।

पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई हुई आसान

रायपुर (आरएनएस)। किसान 'पैडी ट्रांसप्लांटर' से धान की रोपाई आसानी से कर सकते है। इसके उपयोग से न्यूनतम लागत और कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते है। उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम मानिकपुर, रिसेवाड़ा और श्रीगुहान के किसानों के खेतों में कृषि अभियांत्रिकी व कृषि विज्ञान केन्द्र के मार्गदर्शन में लगभग 25 एकड़ में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई का कार्य बड़ी ही सरलता से किया गया। किसान बालमुकुन्द ने बताया कि पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई बहुत ही आसान है। मैट टाइप नर्सरी तैयार करने में मात्र दो मजदूरों के साथ 18 दिन में ही नर्सरी तैयार हो गई। वहीं ग्राम अंजनी निवासी उजियार सिंह वट्टी द्वारा महज 5 घंटे में दो मजदूरों के साथ एक एकड़ में धान रोपाई का काम पूर्ण कर लिया गया। इस विधि से न्यूयतम लागत और कम समय में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है।

बोधघाट परियोजना के नाम पर जनप्रतिनिधि दूरी बना रहे हैं - प्रकाश ठाकुर

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के बोधघाट परियोजना शुरू होने की खबरों के बीच प्रभावित गांवों में हलचल शुरू हो गयी है। बस्तर संभाग सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि बोधघाट परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बस्तर संभाग के जन प्रतिनिधियों के साथ समाज की बैठक बुलायी गयी थी। बोधघाट परियोजना वास्तव में बस्तर के हित में है या नहीं इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त करना था।

ट्री गार्ड बनाने के लिए बांस की कटाई अवैध

बीटगार्ड शेखर रात्रे ने वन अपराध में नहीं दिया अधिकारियों का साथ

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रान्त अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण कुमार भारती, प्रान्तीय महामंत्री प्रशासन एवं समन्वय के आर डहरिया, प्रदेश सचिव डॉ, अमित मिरी, जिलाध्यक्ष कोरबा के डी पात्रे एवं विकास खंड शाखा अध्यक्ष कटघोरा सुरेन्द्र कुमार खुंटे ने ट्री गार्ड बनाने के लिए बांसों की कटाई को अवैध कहा है। खुंटे ने उप वनमंडल अधिकारी पाली वाई पी डडसेना के द्वारा किए गए जांच को पक्षपातपूर्ण तथा मूल तथ्यों से भटकाने वाला बताते हुए राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अनुसार कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत बाकी क्षेत्र में हल्दीबाड़ी बांसबाड़ी आरएफ 790 में बांसों की कटाई कराई गई थी जिसमें जांच पूर्ण होने की जानकारी मिल रही है। इस कटाई के लिए डीएफओ कटघोरा द्वारा विभागीय अनुमति ली गई थी। इससे पहले डीएफओ कटघोरा ने मीडिया में बयान दिया था कि सूखे तथा टेढ़े बांसों की छंटाई करा रहे थे। फिर बयान बदलकर कहने लगे ट्री गार्ड बनाने के लिए बांस कटाई कराया गया था, कटाई का उद्देश्य चोरी नहीं था। यदि चोरी नहीं था तो कटाई का आदेश बीटगार्ड शेखर सिंह रात्रे को क्यों नहीं दिया गया। शेखर रात्रे को मरवाही क्यों भेजा गया। जांच अधिकारी वाईपी डडसेना उप वनमंडल अधिकारी पाली ने जांच किया। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि विभागीय अनुमति से बांस

की कटाई ट्री गार्ड बनाने के लिए किया गया था। महिला स्व सहायता समूह एवं वन समितियों के द्वारा बांस ट्री गार्ड का निर्माण किया जाना बताया गया है। जिसमे उन्होंने दोनों पक्ष का बयान लेने की बात कही है तथा रेंजर एवं डिप्टी रेंजर को क्लीन चिट देने की बात कही है। मामला अवैध बांस कटाई का है, जिसे वनरक्षक शेखर रात्रे एवं रेंजर मृत्युंजय शर्मा के बीच का विवाद बता वन अपराध एवं घोटाला पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है, और बलि का बकरा बनाया जा रहा है बीटगार्ड शेखर रात्रे को, जिसे उसके इस साहसिक कदम के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अनुसार पीसीसीएफ द्वारा भी रेंजर एवं वनरक्षक के बीच का आपसी विवाद बताया जा रहा है क्योंकि उनको जांच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट भेजी गई है। यदि बांस की कटाई ट्री गार्ड बनाने के लिए विभागीय अनुमति से हो रही थी तो यह अनुमति किस अधिकारी ने जारी किया था? कितना बांस काटा जाना था? मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किस मद से किया जाना था? इस बिंदु पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है? यदि शेखर रात्रे के परिसर क्षेत्र से विभागीय अनुमति से बांस कटाई करनी थी तो बीट गार्ड शेखर रात्रे को मरवाही क्यों भेजा गया था? बीट गार्ड रात्रे को भी तो बांस कटाई का आदेश दिया जा सकता था, परंतु बीट गार्ड रात्रे की अनुपस्थिति में उसके बीट क्षेत्र में बिना उसकी जानकारी केकटाई कराई जा रही थी इस कारण कटाई के जिम्मेदारी शेखर रात्रे की ही है। चाहे स्वयं वन मंडल अधिकारी ही क्यों ना हो? अपने किसी भी परिसर से बिना बीट गार्ड की उपस्थित रहे वनों की कटाई नहीं करा सकते।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल बनेंगे 1,57,815 मकान

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लाख 57 हजार 815 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के संचालक एस. प्रकाश ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों को इस वर्ष योजना के तहत बनने वाले मकानों की जानकारी भी भेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश में बनने वाले कुल एक लाख 57 हजार 815 मकानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के 74 हजार 696, अनुसूचित जाति वर्ग के 20 हजार 042, अल्पसंख्यक वर्ग के 850 और अन्य वर्गों के हितग्राहियों के 62 हजार 227 मकान शामिल हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में बालोद, बस्तर, कांकेर, सूरजपुर और कोरिया जिले में कुल सात-सात हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में साढ़े नौ हजार, बलरामपुर-रामानुजगंज में चार हजार, बेमेतरा और मुंगेली में पांच-पांच हजार, बीजापुर में 250, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद और रायगढ़ में नौ-नौ हजार, दंतेवाड़ा में तीन हजार, धमतरी में 3600, दुर्ग में 3557, गरियाबंद और राजनांदगांव में सात-सात हजार, जशपुर और कोरबा में आठ-आठ हजार, कबीरधाम में साढ़े चार हजार, कोंडागांव में 4100, नारायणपुर में 285, रायपुर में 523, सुकमा में डेढ़ हजार तथा सरगुजा जिले में 12 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई हुई आसान

न्यूनतम लागत और कम समय में अधिक उत्पादन, प्रति एकड़ तीन हजार रूपए अनुदान की पात्रता

रायपुर (आरएनएस)। किसान 'पैडी ट्रांसप्लांटर' से धान की रोपाई आसानी से कर सकते है। इसके उपयोग से न्यूनतम लागत और कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते है। उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम मानिकपुर, रिसेवाड़ा और श्रीगुहान के किसानों के खेतों में कृषि अभियांत्रिकी व कृषि विज्ञान केन्द्र के मार्गदर्शन में लगभग 25 एकड़ में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई का कार्य बड़ी ही सरलता से किया गया। किसान बालमुकुन्द ने बताया कि पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई बहुत ही आसान है। मैट टाइप नर्सरी तैयार करने में मात्र दो मजदूरों के साथ 18 दिन में ही नर्सरी तैयार हो गई। वहीं ग्राम अंजनी निवासी उजियार सिंह वट्टी द्वारा महज 5 घंटे में दो मजदूरों के साथ एक एकड़ में धान रोपाई का काम पूर्ण कर लिया गया। इस विधि से न्यूयतम लागत और कम समय में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के नवीन फसल प्रदर्शन

योजना के तहत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से किसानों के खेतों में नर्सरी तैयार व रोपाई कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3 हजार रूपए अनुदान का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि इस विधि द्वारा एक एकड़ में धान रोपाई का कार्य मात्र 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है और साधारण खेती की अपेक्षा लागत भी कम आता है। साथ ही उत्पादन में 10-12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी होती है।

आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई की घोषणा

रायपुर (आरएनएस)। आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद शशि थरूर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के मार्गदर्शन में आल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने अपनी प्रदेश कार्यकारणी की घोषणा की जिसमें 10 लोगों को स्थान दिया गया है। इसमें मुकेश चंद्राकर और अजय श्रीवास्तव को समन्वयक, दीप सारस्वत को समन्वयक (सोशल मीडिया एवं संचार), स्नेहिल भारद्वाज को समन्वयक (कार्यक्रम व आयोजन), रवि गवलनी को समन्वयक (वित्तीय), सुदीप मैटर को समन्वयक (अनुसंधान), प्रणव दास को समन्वयक (समन्वय एआईपीसी इकाई) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं संभाग अनुसार शिल्पराज देवांगन को समन्वयक (सदस्यता विस्तार ,रायपुर), रणविजय सिंह देव को समन्वयक (सदस्यता विस्तार, सरगुज़ा), निखिल शाह को समन्वयक (सदस्यता विस्तार ,दुर्ग) नियुक्त किया गया है।

राजधानी रायपुर में एडीजी के बेटी और पत्नी मिली कोरोना संक्रमित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है. कुछ दिन पहले नक्सल डीआईजी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, अब एडीजी योजना प्रबंध की पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। वरिष्ठ आईपीएस अफसरो के घर में कोरोना के केस मिलने के बाद हड़कम्प मच गया है। लॉकडाउन की वजह से अभी एडीजी योजना प्रबंध आफिस नहीं जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के पहले एडीजी लगातार आफिस आ रहे थे। हालाँकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ आम सर्वेंट काम नही करते। पुलिस बटालियन के जवान घरों में काम करते हैं।संभावना है कि उन जवानों से ही अफसरों के घरों में संक्रमण पहुंच रहा है। रायपुर के शांति नगर में रहने वाले एडीजी की बेटी और पत्नी कोरोना संक्रमित मिली है लॉकडाउन के चौथे दिन राजधानी

के कंटेनमेंट जोन को फोकस कर की गई कोरोना की जांच और लिए गए आठ सौ से ज्यादा सैंपल में सवा दो सौ से ज्यादा मरीज सामने आ गए। जिले में कुल 244 नए मरीजों का पता चला है। राजधानी के हॉट स्पॉट मंगलबाजार में 27, माना बस्ती में 13 डंगनिया में 9 तथा रामकुड में 6 मरीजों की पुष्टि है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने व्यापक स्तर में रेंडम जांच किया गया है, जिसमें अब तक के सबसे ज्यादा 244 कोरोना मरीज सामने आए हैं। राजधानी में जिला अस्पताल,मलेरिया अधिकारी को , एम्स के अलावा एक प्रायवेट डाक्टर को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं ईओडब्लू में पदस्थ एक उपनिरीक्षक को कभी संक्रमित पाया गया है। पंडरी कपड़ा मार्केट के कपड़ा दुकान के दो संचालक सहित तीन लोगों को भी संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज माना बस्ती में जाकर जांच की। शिविर लगाकर लगभग पचास लोगों के सैंपल लिए गए जिसमें से 13 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

क्रय धान भुगतान के एवज में दिया चेक बाउंस

महासमुंद (आरएनएस)। गबन के आरोप में बागबाहरा पुलिस ने गुरुवार को राकेश को गिरफ्तार किया। इस मामले में 14 अक्टूबर को शिकायत हुई थी। थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी के अनुसार धान खरीदी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के इस मामले में बागबाहरा थाने में कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा के मण्डी निरीक्षक द्वारा की गई शिकायत में लगभग 61 लाख रुपये गबन का मामला दर्ज था। बागबाहरा, पिथौरा तथा महासमुन्द मण्डी क्षेत्र के किसानों ने मण्डी कार्यालय बागबाहरा में लिखित शिकायत दर्ज कराई बाद मंडी ने पुलिस से शिकायत की। मिली जानकारी के अनुसार रबी फसल का धान राकेश चौहान (चण्डी मेडिकल बागबाहरा) ने क्रय किया है तथा क्रय धान के भुगतान के एवज में चण्डी मेडिकल बागबाहरा के नाम से चेक दिया।

पात्र हितग्राहियों को मिलेगा निःशुल्क राशन

लगभग पौने तीन लाख पात्र राशनकार्डधारी होंगे लाभान्वित

महासमुंद (आरएनएस)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में (सामान्य एपीएल श्रेणी के राशन कार्डो को छोड़कर) माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक प्रतिमाह अतिरिक्त चावल एवं चना आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि जुलाई से नवम्बर माह तक उपरोक्त श्रेणी के राशन कार्ड को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की अधिकतम मात्रा के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि माह जुलाई 2020 के अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण माह अगस्त 2020 के नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन एवं वितरण के साथ किया जाएगा। उपरोक्त राशन कार्ड में जुलाई से नवंबर 2020 तक 1 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पूर्ण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्रों में प्रदाय किये जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 1 किलोग्राम चना निः शुल्क तथा 1 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जाएगा।

नजूल पट्टा के नवीनीकरण के साथ सड़क पुल निर्माण कार्य को भी देखेंगे एडीएम

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर मती किरण कौशल ने जिला मुख्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियो को विभिन्न कार्य प्रभार व जिम्मेदारी सौंपी है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा की अनुपस्थिति में कलेक्टर कोरबा के प्रभार में संजय अग्रवाल अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रहेंगे। संजय अग्रवाल को राष्ट्रीय राजमार्ग, लोकनिर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क, भवन एवं पुल-पुलियों के निरीक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। अपर कलेक्टर मती प्रियंका महोबिया रेल कॉरिडोर परियोजना और भू-अर्जन पुनर्वास का काम देखेंगी। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार को कृषि, पंचायत एवं उससे संबंधित विभाग के अलावा रेशम, मत्स्य विभाग और गोधन न्याय योजना तथा नरवा-गरवा-घुरवा बाड़ी योजना का भी दायित्व सौंपा गया है। जिला पंचायत सीईओ कोरबा के अनुपस्थिति में संजय अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के प्रभार में रहेंगे। जारी आदेशानुसार संजय अग्रवाल अपर कलेक्टर को अनुभाग कोरबा एवं कटघोरा के अंतर्गत तहसील करतला एवं पाली के अंतर्गत राजस्व दायित्व सौपे गए है। अग्रवाल को हिन्दू विवाह के अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। अग्रवाल पासपोर्ट से संबंधित कार्यो के प्रभारी अधिकारी भी होंगे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU